(b) Rajasthan, Punjab, Union Territory of Delhi, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have been affected so far. The damage caused to crops is estimated to be Rs. 1,52,000 over an area of 10,000 acres in Uttar Pradesh. Information about other affected areas is awaited from the respective State Governments.

(c) A statement is laid on the Table. [*See* Appendix I, annexure No. 12].

(d) None.

परिवहन उपक्रम

*८१. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री व० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवाओं की कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिये कोई अध्ययन समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो सदस्यों के नाम क्या है; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र से राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवाओं को प्रोत्साहन देने की मांग की है; और यदि हां, तो किन राज्यों ने तथा किस प्रकार के प्रोत्साहन की मांग की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). अक्तूबर, १९६१ में आंध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया था कि आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (और दूसरे प्रदेशों के ऐसे कारपोरेशनों) को आय कर से छूट दे दी जाये। यह सुझाव परिवहन विकास परिषद् की अक्तूबर १९६१ की बैठक में रखा गया था। परिषद ने सिफारिश की कि जिन सड़क परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया है उन की कठिनाइयों के अध्ययन के लिय एक सरकारी समिति बनाई जाये जो यह सुझाव देगी कि इन्हें कर मुक्ति के रूप में या अन्यथा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यह विषय विचाराधीन है ।

Agricultural Production

*82. **Shri Basumatari:**
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Bhakt Darshan:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government have under consideration the proposal that an inducement for increased production (quantitative as well as qualitative) should be provided to State Governments by linking the quantum of Central Grants to the States with performance in the field of agriculture;

(b) whether it is also a fact that there is a proposal to review agricultural production at a high level after every three months to eliminate bottlenecks and prevent shortfalls; and

(c) if so, when it is likely to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) The Central grants to States for their agricultural programmes, each year, are governed, among other things, by the patterns of financial assistance prescribed for different schemes, the agreed outlays thereunder, and the progress of expenditure under the different sub-heads of development.

(b) and (c). The progress of major production programmes is already being reviewed at periodical intervals at different levels.